5 अक्टूबर, 2017

SCO के विस्तार से अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं में वृद्धि

*डॉ. अतहर ज़फ़र**

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने अपने 17 वें सम्मेलन का आयोजन कज़ाकिस्तान के आस्ताना में जून 2017 में किया था, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। भारत 2005 से संगठन का पर्यवेक्षक रहा है। अस्ताना सम्मेलन में भारत को SCO की पूर्ण सदस्यता दी गई। पाकिस्तान को भी संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया। दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्र में विशाल आबादी वाले दो देशों को बीजिंग स्थित मध्य एशिया केंद्रित समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। संयोग से 2005 में अस्ताना में ही आयोजित सम्मेलन में इन दोनों देशों तथा ईरान को SCO के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि यह अपेक्षित और प्रत्याशित है, फिर भी सदस्यता में विस्तार के कारण यूरेशिया तथा अन्य देशों के साथ भारत का सम्बंध व्यापक होने की संभावना है।

इस सदी के प्रारम्भ में गठन से लेकर अब तक करीब डेढ़ दशक में SCO का ये पहला, लेकिन महत्त्वपूर्ण विस्तार है, विशेष कर आर्थिक, जनसांख्यिकीय तथा भौगोलिक दृष्टि से। संगठन का विस्तार अब हिंद महासागर से आर्कटिक क्षेत्र तथा प्रशांत महासागर से काला सागर क्षेत्र तक हो चुका है। बैठक के लिए प्रस्थान करने से पहले प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 'सदस्यता विस्तार के बाद SCO दुनिया की लगभग 42% आबादी, जीडीपी का 20% तथा भूमि के 22% भाग का प्रतिनिधित्व करेगा'। प्रधान मंत्री ने SCO में भारत की पूर्ण सदस्यता को एक 'ऐतिहासिक कदम' बताया।

SCO की पृष्ठभूमि

15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर-सरकारी बहुपक्षीय मंच के रूप में SCO के गठन की घोषणा की गई थी। पहले इसके पांच सदस्यों - चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस तथा ताजिकिस्तान को "शंघाई फाइव" कहा जाता था। शंघाई फाइव की स्थापना 1996 में मुख्य रूप से चीन, रूस तथा मध्य एशियाई क्षेत्र के नए स्वतंत्र पांच देशों के बीच सीमा मुद्दों के निपटारे के लिए की गई थी, जिनमें कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य तथा

ताजिकिस्तान के साथ चीन की सीमाएं मिलती थीं। सोवियत संघ के भाग के रूप में पूर्व के विशाल पड़ोसी देश के साथ इनकी सीमाएं अरेखांकित थीं। 'Treaty on Deepening Military Trust in Border Regions' तथा 'Treaty on Reduction of Military Forces in Bordering Regions' के अन्तर्गत इसको कायम किया गया था। 2001 में शंघाई फाइव में उज़्बेकिस्तान को शामिल कर इसे SCO का रूप दिया गया। वर्तमान समय में SCO में आठ पूर्ण सदस्य हैं: भारत, चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान। इसके पर्यवेक्षक राज्य हैं अफ़ग़ानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया।

संगठन में संवाद साझेदार हैं अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की तथा श्रीलंका। मध्य एशिया के पांच गणराज्यों में सिर्फ तुर्कमेनिस्तान सदस्य देश के रूप में संगठन में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि, इसके नेता नियमित रूप से SCO बैठकों में भाग लेते रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, 'स्थायी तटस्थता' की नीति पालन करता है, जोकी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1995 में अनुमोदित भी किया गया है।

2003 में लागू हुए SCO घोषणापत्र का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास तथा पड़ोसी धर्म को मजबूत करना है। सहयोग में बढ़ोत्तरी के क्षेत्र में राजनीति, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। घोषणापत्र में इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने एवं इन्हें सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास को भी शामिल किया गया है। साथ ही ये एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष तथा तर्कसंगत नई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर बढ़ रहा है।

स्टेट काउंसिल SCO में निर्णय लेने की लिए सर्वोच्च इकाई है। इसकी वार्षिक बैठक में सभी SCO मामलों के निर्णय लिये जाते हैं तथा दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। इसके बाद दूसरी इकाई SCO की सरकार के प्रमुखों की परिषद है। इसकी बैठक भी वार्षिक होती है। SCO की इस परिषद में वार्षिक बजट को मंजूरी दी जाती है, बहुपक्षीय सहयोग की रणनीति तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जाती है एवं महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सहयोग के मुद्दे संबोधित किये जाते हैं। SCO संसद के प्रमुखों, सुरक्षा परिषदों के सचिवों, विदेश मामलों के मंत्रियों, रक्षा, आपात राहत, अर्थव्यवस्था, परिवहन, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अदालतों के प्रमुखों एवं अभियोजन पक्ष के वकीलों के लिए भी बैठकों का आयोजन करता है। सदस्य देशों की राष्ट्रीय समन्वय परिषद (CNC) SCO में समन्वय तंत्र के लिए मंच का कार्य करती है।

बीजिंग में स्थित SCO सचिवालय तथा ताशकंद स्थित कार्यकारी समिति की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS), दो स्थायी निकाय हैं। SCO महासचिव तथा RATS की कार्यकारी समिति के निदेशक, राज्य परिषद के प्रमुखों द्वारा तीन साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। राशिद अलीमोव (ताजिक्स्तान) तथा येवगेनी सेसोयेव (रूस) 1 जनवरी 2016 से इन पदों पर विराजमान हैं। वर्तमान समय में SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी तथा चीनी हैं, लेकिन दक्षिण एशिया के एक अरब से ज्यादा लोगों के होने से इसकी भाषाई विविधता विस्तृत होने की संभावना है।

नए सदस्यों से SCO की वित्तीय प्रोफाइल में योगदान देने तथा वृद्धि करने की भी उम्मीद है। इसका वित्तीय पोषण सदस्यों द्वारा 'विशेष समझौते' के अनुसार 'मूल्य साझाकरण' सिद्धांत के अनुरूप किया जाता है। सदस्य देश अपने प्रतिनिधियों तथा SCO गतिविधियों में विशेषज्ञों की भागीदारी से संबंधित अपना खर्च वहन करते हैं। SCO के बजट में रूस (24%)तथा चीन (24%)लगभग आधा योगदान देते हैं, जबकि कज़ाकिस्तान, उज़बेकिस्तान, किर्गिस्तान तथा ताजिकिस्तान क्रमश: 21%, 15%, 10% तथा 6%का योगदान देते हैं। हालांकि SCO में निर्णय सदस्य देशों में समानता के आधार पर लिये जाते हैं, फिर भी अधिक योगदान देने वाले देश संगठन की संरचना में ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। आठ-सदस्यीय संगठन में भारत तथा पाकिस्तान जैसी क्रमश: दूसरी तथा चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शामिल होने से SCO में योगदान के तौर-तरीके बदल सकते हैं। इनकी जीडीपी क्रमश: अमेरिकी डॉलर 2.2 ट्रीलियन तथा अमेरिकी डॉलर 283 बीलियन (विश्व बैंक, 2016) है। हालांकि संगठन चलाने के लिए बजट के बारे में सार्वजनिक जानकारी काफी कम है, फिर भी एक अनुमान के अनुसार 2015 में इसका बजट अमेरिकी डॉलर 4 मीलियन था।

SCO का विकास

प्रारम्भ में SCO ने अपनी क्षमता, ताकत तथा तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद तथा SCO क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर-क्षेत्रीय संबंधों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही अन्य समूहों के साथ सम्बंध स्थापित किया गया। सदस्य देशों के सामने ये तत्काल समस्याएं थीं। शीघ्र ही SCO ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। 2004 में इसके स्थायी निकाय, सचिवालय तथा RATS का गठन किया गया। इन गतिविधियों में 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों तथा अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें बाद में मध्य एशियाई देश भी शामिल हो गए थे।

प्रारम्भ में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के बाद SCO ने सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार करना आरम्भ किया। 2003 में क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग में विस्तार आदि मुद्दे शामिल किये गए। 2005 के बाद से बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ उद्देश्यों में विस्तार किया गया। ये समझ विकसित हुई कि मात्र सुरक्षा सरोकार ही काफी नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए आर्थिक विकास भी आवश्यक है। इसके लिए विस्तृत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, परिवहन सुविधा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान दिया जाने लगा। 2008 में SCO की दुशान्बे में हुई बैठक में SCO के इंटरबैंक एसोसिएशन तथा यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच साझेदारी के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

2010 में SCO ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, परिवहन तथा संचार के संयुक्त परियोजनाओं के मुद्दों से निपटने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। अपनी स्थापना के 15 वें वर्ष में इसने वित्त, बैंकिंग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जिसमें वैकल्पिक तथा नवीकृत ऊर्जा स्रोत भी शामिल थे, कस्टम्स, कृषि, परिवहन तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में 'व्यावहारिक सहयोग' बढ़ाने पर बल दिया। SCO ने SCO विकास रणनीति 2025, SCO

सदस्यों के बीच व्यापार तथा अर्थव्यवस्था में बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रम, कार्यान्वयन के लिए योजना तथा 2012-16 के लिए SCO के ढांचे में परियोजनाओं व क्रियाकलापों में वृद्धि समेत 'व्यावहारिक कार्यान्वयन' की आवश्यकता पर बल देते हुए दीर्घकालिक नीतियां अपनानी शुरु दीं।

बहुपक्षीय सहयोग में अनुभव प्राप्त करने तथा संगठन को क्षेत्रीय एवं वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में मजबूत बनाने की आवश्यकता समझने के बाद, जहां दक्षिण एशिया बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है, SCO के सदस्य देशों ने भारत तथा पाकिस्तान को पारस्परिक लाभ तथा संगठन के उद्देश्यों को लाभान्वित करने के लिए पूर्ण सदस्यता दी।

आस्ताना शिखर सम्मेलन (2017)

आस्ताना शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय और बहुपक्षीय – दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। सम्मेलन ने भारत तथा पाकिस्तान की पूर्ण सदस्यता को 'ऐतिहासिक' प्रकृति का बताते हुए इस पर विचार किया। आस्ताना की बैठक में 11 दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया, जिनमें आस्ताना घोषणापत्र, उग्रवाद निरोध पर SCO सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के संयुक्त प्रतिरोध पर वक्तव्य, 2017-2018 के लिए SCO के सदस्य देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में संयुक्त कार्य-योजना कार्यान्वित करना शामिल हैं। इनके अलावा SCO सचिवालय और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला SCO शिखर सम्मेलन जून 2018 में चीन में आयोजित होना है। इसके नियमों के अनुसार राष्ट्रपति में भी बदलाव होगा। SCO का अध्यक्ष हर साल बदलता है और इस समय चीन अध्यक्ष है।

आतंकवाद और उग्रवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई SCO में सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। यह सदस्य देशों में आतंकवाद विरोधी अंतर-संचालन बढ़ाने के लिए नियमित रूप से आतंकवाद विरोधी अभ्यास करता है। आतंकवाद का संकट किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि, यह क्षेत्रीय तथा क्षेत्र से इतर भी फैल चुका है। लिहाजा इस क्षेत्र को विस्तृत रूप से सम्बोधित करना आवश्यक है तथा इस संदर्भ में SCO की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। आस्ताना की बैठक इस चुनौती से निपटने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसमें 9 जून 2017 को SCO के सदस्यों ने एक ठोस कदम के रूप में कट्टरपंथ विरोधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। प्रशासनिक तथा कानूनी पहलुओं को शामिल करते हुए सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करना है, ताकि आधुनिक खतरों का सामना किया जा सके, सभी सदस्य देशों की सुरक्षा में वृद्धि हो, उनकी सुरक्षा सेवाओं के बीच प्रभावशाली सहयोग स्थापित हो तथा संबंधित कानून बेहतर बन सकें। SCO के सदस्यों ने आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों तथा संगठनों की गतिविधियों के ख़िलाफ़ सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई है।

आस्ताना शिखर सम्मेलन ने परिवहन में बहुपक्षीय सहयोग का विकास, अंतरराष्ट्रीय मार्गों को नया तथा आधुनिक बनाकर परिवहन तथा संचार क्षमता में विस्तार, रेलवे का विकास, उच्च गति ट्रेनों तथा मल्टीमॉडल

लॉजिस्टिक्स केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। SCO ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन पर एक अंतर-सरकारी समझौता किया, जो जनवरी 2017 से लागू हुआ है। दक्षिण एशिया में SCO के विस्तार से मध्य एशिया से नए सदस्य देशों के सड़कों, रेलों तथा बंदरगाहों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निर्यात की संभावनाएं खुलती हैं।

SCO तंत्र द्विपक्षीय सम्बंधों और आपसी समझ में सुधार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। आस्ताना शिखर सम्मेलन भी इस मोर्चे पर उपयोगी साबित हुआ है। दूसरी ओर, भारत तथा चीन के नेताओं ने विचार-विमर्श कर 'आस्ताना सहमति' स्थापित की, जिसमें मतभेदों को सीमित करने तथा उन्हें रोकने के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी। साथ ही ये नेता क्षेत्र में सहयोग तथा विकास के लिए कार्यों पर भी सहमत हुए। भारत-पाकिस्तान के सम्बंध भी कभी-कभी उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं। SCO सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय सम्बंधों में आत्मविश्वास और सुधार लाने के अवसरों की सुविधाएं प्रदान कर सकता है।

हाल में मध्य एशियाई देशों के बीच आपसी सम्बंध बेहतर हुए हैं तथा ये माना जा सकता है कि SCO क्षेत्र में नेताओं की वार्षिक बैठक ने द्विपक्षीय मतभेदों को दूर करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद की है। आस्ताना शिखर सम्मेलन ने इस क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया है तथा SCO सदस्यों के बीच आपसी हितों को प्रोत्साहन देने के लिए दीर्घकालीन पड़ोसी धर्म, मित्रता तथा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है, जिसमें एक-दूसरे से लगी सीमाओं पर शांति तथा मित्रता भी शामिल है।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण से आस्ताना में हुए 2017 के शिखर सम्मेलन ने अफ़ग़ानिस्तान तथा इस क्षेत्र में विकास पर अपना रुख स्पष्ट किया। आस्ताना सम्मेलन ने अफ़ग़ानिस्तान में SCO Contact Group के प्रयासों को अपना समर्थन दिया। इसने उस देश में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी जोर दिया। अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति अब भी नाज़ुक है। जबकि नए ट्रम्प प्रशासन के नेतृत्व में अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में अपनी नई भूमिका 'राष्ट्र निर्माण' में सहयोग से बदलकर 'आतंकवादियों का संहार' करना तय किया है। अफ़ग़ानिस्तान के आस-पास बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वो युद्धग्रस्त देश के उत्थान के लिए आगे बढ़ें। SCO के मंच से तथा मध्य एशियाई गणराज्यों की सहायता से भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान तथा ईरान - अफ़ग़ानिस्तान में शांति तथा स्थायित्व बहाल करने में मदद कर सकते हैं। अफ़ग़ानिस्तान में पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया तथा मध्य एशिया से सामानों, सेवाओं, विचारों तथा लोगों के आवागमन का केन्द्र बनकर उभरने की पूरी संभावना है। आस्ताना बैठक में अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ ग़नी ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान एशिया के केन्द्र में स्थित है, तथा दक्षिण एशिया जाने के लिए मुख्य द्वार के रूप में ये प्राकृतिक रूप से 'क्षेत्रीय केन्द्र' का कार्य कर सकता है।

SCO के सदस्य के रूप में भारत

SCO की पूर्ण सदस्यता भारत, क्षेत्र तथा संगठन के लिए कई दृष्टि से लाभदायक साबित होगी। नए देश की सदस्यता पुराने तथा नए दोनों तरह के सदस्यों के लिए लाभदायक है। आस्ताना में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं SCO के साथ भारत के प्रगाढ़ सम्बंधों को लेकर आशान्वित हूं, जो अन्य मसलों के अलावा अर्थव्यवस्था, संचार तथा आतंकवाद-रोधी कार्यक्रमों में सहयोग ला सकता है"। निश्चित रूप से, भारत ने कई भौगोलिक-रणनीतिक मुद्दों, आर्थिक हितों, जिसमें ऊर्जा, दूसरे क्षेत्रों में सांस्कृतिक प्रसार जैसे मुद्दे शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए संगठन का सदस्य बनना स्वीकार किया है, जिसमें उपमहाद्वीप के कई साझा मुद्दे शामिल हैं। पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने से यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के प्रभाव में वृद्धि हुई है तथा ये क्षेत्र की सुरक्षा तथा आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए मंच प्रदान करता है।

सीधे सड़क सम्पर्क के अभाव ने मध्य एशिया तथा अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के व्यापार को प्रभावित किया है। SCO भारत का सम्पर्क अफ़ग़ानिस्तान, मध्य एशिया तथा यूरेशिया के साथ बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है, जिससे व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य आर्थिक सरोकार लाभान्वित हो सकते हैं। भारत, किर्गिस्तान के बिशकेक में 2012 में हुई पहली भारत-मध्य एशियाई वार्ता में 'कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया नीति' की घोषणा कर चुका है। इस क्षेत्र के साथ सम्पर्क बढ़ाना इस नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बंधों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने सम्पर्क जोड़ने के कई साधनों की शुरुआत की है, जिनमें SCO के प्रावधान भी शामिल हैं। सम्पर्क का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने SCO में अपने भाषण में कहा कि SCO देशों के साथ सम्पर्क एक 'प्राथमिकता' है तथा अंतरराष्ट्रीय उत्तरी-दक्षिणी परिवहन मार्ग (INSTC) में भारत की भागीदारी, चाबाहार संधि एवं अश्गाबट संधि में शामिल होने की उसकी इच्छा देश को इस क्षेत्र के और करीब लाएगी।

अर्थव्यवस्था तथा सम्पर्क सुविधा के अलावा SCO में शामिल होकर भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं भी सुरक्षित देखता है। विशेषकर आगे बनने वाले SCO ऊर्जा क्लब के ज़रिये। इस सम्बंध से मध्य एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप के बीच ऊर्जा सहयोग में मदद मिलेगी। इस क्लब में दोनों तरह के, दुनिया के विशालतम ऊर्जा उत्पादक तथा सर्वाधिक ऊर्जा खरीदनेवाले देश शामिल हैं। SCO ऊर्जा क्लब के हिस्से के रूप में विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था पड़ोस में स्थित दुनिया के विशालतम ऊर्जा उत्पादक देश से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। SCO ऊर्जा क्लब खरीदनेवालों तथा बेचनेवालों के लिए दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा स्थापित कर सकता है। ऊर्जा सप्लाई में संयोजन तथा बेहतर कीमत का तंत्र बेहतर आर्थिक उत्पादकता में मददगार साबित होगा।

SCO अपने विशाल तेल, गैस तथा आण्विक सामग्री भंडार के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके सदस्य देशों के पास अंतरराष्ट्रीय तेल भंडार का करीब 25%, प्राकृतिक गैस भंडार का 50% से अधिक, लगभग एक-तिहाई कोयला तथा विश्व का करीब 50% ज्ञात यूरेनियम भंडार उपलब्ध है। प्रारम्भ में SCO सदस्य देशों के साथ व्यापार में ऊर्जा विनिमय की व्यवस्था स्थापित करने की संभावना

खंगाल सकता है, बाद में ये व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार में उत्पादकों, प्रसंस्करण करनेवालों तथा खरीदारों के साथ भी लागू की जा सकती है।

क्षेत्रीय विकास तंत्र सुनिश्चित करने के लिए SCO पारम्परिक तथा ग़ैर-पारम्परिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की प्रक्रिया भी विकसित कर रहा है। सदस्य देश आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों की तस्करी तथा सम्बंधित सुरक्षा चुनौतियां झेल रहे हैं। ये चुनौतियां किसी भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित नहीं हैं। लिहाजा क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे खतरों का सामना करने के लिए बहु आयामी कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। हालांकि RATS विभिन्न आशंकित स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न स्थानों पर नियमित अभ्यास करता है, फिर भी SCO के भीतर हिंसा को रोकने तथा आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया जानकारियां साझा करने की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने से अफ़ग़ानिस्तान को स्थिर बनाने में बेहतर संयोजन किया जा सकता है। इस देश में सुरक्षा, स्थिरता तथा शांति बहाल करना पड़ोसी देशों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्थायित्व में विलम्ब, राजनीतिक अनिश्चितता तथा आर्थिक परेशानियां आसपास के क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया के बीच प्रभावशाली ऊर्जा सहयोग एवं सामग्रियों की आवाजाही के लिए अफ़ग़ानिस्तान में शांति आवश्यक है। अन्य SCO सदस्यों के साथ मिलकर भारत यहां स्थिरता लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत, अफ़ग़ानिस्तान में सर्वाधिक क्षेत्रीय दाता तथा सबसे बड़ा निवेशक है, जो कि 2 बीलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। चीन, कज़ाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान सहित अन्य SCO सदस्य देश भी अफ़ग़ानिस्तान के विकास के लिए निवेश कर रहे हैं। एक पैन-SCO प्रयास से तालमेल तथा धन की अधिक उपयोगिता हो सकती है। SCO क्षेत्रवार सहयोगात्मक ढांचा तैयार कर सकता है, ताकि देश में ढांचागत विकास तथा दीर्घकालीन रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकें। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि SCO क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर शांति एवं सुरक्षा के मुख्य स्तंभों में एक है।

भारत को शामिल करने पर SCO का दृष्टिकोण

एक दशक तक SCO का पर्यवेक्षक बने रहने के बाद सदस्य देश इस बात से आश्वस्त हो गए होंगे कि पूर्ण सदस्य के रूप में भारत महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत जैसे विशाल देश के शामिल होने से किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्त्व बढ़ जाता है, उसकी बातें गंभीरतापूर्वक सुनी जाती हैं तथा वो अधिक संतुलित एवं मजबूत बनता है। विस्तार से उसका कद बढ़ता है, उसकी राजनीतिक एवं आर्थिक महत्ता बढ़ती है, तथा वो एक प्रभावशाली गुट बन सकता है। भारत के SCO का पूर्ण सदस्य बनने के कई कारण हैं। उसने तीन बुराइयों - आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद के ख़िलाफ़ SCO की प्रतिबद्धता का समर्थन किया है। भारत SCO सदस्यों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं से अवगत है तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सबसे आगे रहा है।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य से, अगर SCO एशिया तथा यूरेशिया में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, तो भारत को शामिल करने में ही समझदारी है। SCO देश भारत को सामग्रियों तथा ऊर्जा संसाधनों का बड़ा बाजार मानते हैं। भारत कम लागत तथा उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक में अग्रणी है, जिनमें आईसीटी, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, ऑटोमोबाइल्स तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र शामिल हैं। उसके पास SCO सदस्यों को विकास तथा अपनी क्षमताओं में तेजी लाने, विशेषकर एसएमई, रसायन, कृषि, दुग्ध तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि करने में मदद देने की क्षमता है। भारतीय उद्यमों ने बड़े व्यवसायों तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने में अपनी जगह बनाई है तथा SCO देश इसकी प्रतिभाओं का उपयोग कर सकते हैं।

भारत के शामिल होने से SCO की पहुंच विभिन्न दिशाओं में विस्तृत होती है। भारत SCO देशों को प्रायद्वीप के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान कर सकता है तथा संगठन के लिए व्यापार, वाणिज्य, अन्वेषण एवं अनुसंधान तथा विकास के अवसर उपलब्ध करा सकता है। दक्षिण एशिया में व्यापार तथा परिवहन के लिए SCO तट लाइनों में काफी वृद्धि हुई है। भारत को शामिल कर SCO उपमहाद्वीप के अन्य देशों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जो अब तक उसके सदस्य नहीं हैं। रूस, ईरान तथा अन्य देशों के साथ भारत ने उत्तरी-दक्षिणी क्षेत्रों के अलावा अफ़ग़ानिस्तान, मध्य एशिया तथा यूरेशिया को जोड़ने के लिए INTSC का शुभारंभ किया है।

सभी SCO सदस्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोगी सदस्य अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षा स्थिति से प्रभावित हैं। अगर SCO अफ़ग़ानिस्तान के लिए भविष्य में किसी महत्वपूर्ण भूमिका की योजना बना रहा है तो भारत को शामिल करना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। भारत, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा अफ़ग़ानिस्तान में भारी-भरकम निवेश कर रहा है। जहां ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान समेत अफ़ग़ानिस्तान के सभी पड़ोसी देश एक या अन्य रूप में जुड़े हैं, SCO देश में सुरक्षा तथा स्थिरता लाने में एक व्यापक क्षेत्रीय राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक रोडमैप तैयार करने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है।

सांस्कृतिक रूप से भारत के पास SCO को समृद्ध बनाने के लिए काफी कुछ है। भारत एक बहु-धार्मिक, बहुभाषी, बहु-जातीय, बहु-सांस्कृतिक तथा एक अरब से अधिक जनसंख्या वाला देश है। कुछेक अपवादों को छोड़कर व्यापक विविधता के बावजूद भारतीय जनता सदियों से सद्भाव से एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर रह रही है। प्रबुद्ध शास्त्र, महान संत, भक्ति आंदोलन, सूफी विचारधारा तथा स्वतंत्रता के लिए सामूहिक संघर्ष ने समरूप संस्कृति और सहिष्णु समाज विकसित करने में काफी योगदान दिया है। ऐसे समृद्ध तथा मूल्यवान अनुभव SCO देशों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, जो वास्तविक या कथित जातीय, धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं।

उपसंहार

SCO का उदय मध्य एशिया में अधिक क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के बढ़ते खतरे, यूरेशिया में हिंसक अलगाववादी आंदोलनों, 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान में युद्ध, पश्चिम एशिया के ऊर्जा उत्पादन में लंबे समय तक तनाव

एवं मध्य एशिया के ऊर्जा सप्लाई के महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में उद्भव के बीच हुआ। अब ये संगठन यूरेशियाई क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच एक व्यावहारिक अंतर-क्षेत्रीय तथा अंतर-सरकारी राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग के मंच के रूप में उभरा है।

हालांकि इसके आठ सदस्यों में से आधी परमाणु सम्पन्न शक्तियां हैं, फिर भी मुख्य रूप से SCO एक सुरक्षा-संचालित संगठन नहीं है। ये आर्थिक मुद्दों तथा गैर-पारम्परिक सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक या अन्य रूप में सभी सदस्य देशों में उपस्थित हैं। अपने गठन के बाद सीमा मुद्दों से लेकर अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा संदर्भों को SCO ने सम्बोधित किया है। ये कहा जा सकता है कि शंघाई फाइव चीन तथा मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करने में सफल रहा है। हालांकि, दूसरी ओर SCO केंद्रीय एशियाई देशों के बीच आपसी सीमा विवाद का हल करने में सफल नहीं हुआ। उदाहरण के लिए ताजिकिस्तान तथा उज़बेकिस्तान और उज़बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच आदि।

ऐसी संभावना नहीं है कि भारत तथा पाकिस्तान के संगठन में शामिल होने से SCO के सामूहिक एजेंडे उपेक्षित होंगे। ये एक बहुपक्षीय संगठन है तथा इसके कई सदस्यों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे मौजूद हैं। लेकिन उन मुद्दों ने न तो विश्वास-निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया है और न ही संगठन में आम मुद्दों पर सहमति बनाने में रोड़ा अटकाया है। बल्कि, SCO के विभिन्न मंचों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग बढ़े हैं, जिससे विश्वास में कमी दूर हो सकती है तथा सदस्यों के बीच आपसी विश्वास में वृद्धि हो सकती है। क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा तथा स्थिरता के क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों की उपस्थिति से द्विपक्षीय मामलों में आर्थिक एकीकरण को प्राथमिकता मिलेगी।

SCO में भारत के शामिल होने से उसकी संभावनाएं विस्तृत होती हैं तथा यह दोनों पक्षों के लिए चुनौतियों की तुलना में अधिक अवसर देनेवाले एवं लाभदायक हैं। सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, संस्कृति तथा संचार पर सहयोग बढ़ने से भारत के लिए संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इनके अलावा, संचार तथा बुनियादी ढांचे की संभावनाओं के संदर्भ में यदि दक्षिण एशिया के सदस्य SCO के अन्य सहयोगी देशों से यूरेशियाई क्षेत्र में विभिन्न सम्पर्क परियोजनाओं में शामिल होते हैं, तो दक्षिण एशिया से मध्य एशिया तथा यूरोप के लिए एक और संभावित मार्ग प्रारम्भ किया जा सकता है। जमीन के रास्ते सम्पर्क में प्रतिबंधों से पूरे क्षेत्र का विकास बाधित हुआ है।

चीन तथा रूस की तुलना में, अन्य SCO सदस्य अपेक्षाकृत छोटे हैं एवं पड़ोस में दो बड़े देशों द्वारा उनके निकट हुई घटनाओं पर अपनाई गई मुद्राओं से मध्य एशियाई देशों में चिंता पैदा हो सकती है। दोनों बड़े देश SCO के दो मुख्य संचालक माने जाते हैं। भारत की सदस्यता एक तरह से संतुलन बनाने तथा संगठन को बहु-ध्रुवीय बनाने में मददगार साबित होगा। आस्ताना में SCO सदस्यों की बैठक ने अधिक 'न्यायसंगत बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था' बनाने पर बल दिया, जो हर देश के हितों को पूरा करता है।

****

** डॉ. अतहर ज़फ़र, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में शोध अध्येता हैं।*

डिस्क्लेमर : आलेख में व्यक्त विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते